

[2015] 12 एस. सी. आर. 304

मेसर्स गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और अन्य

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य

(2015 की सिविल अपील सं 14184-14185)

9 दिसंबर, 2015

[वी. गोपाल गौड़ा और अमिताव रॉय, न्यायाधिपतिगण]

उत्तराखंड कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2012- धारा 27 (ग) (iii) और (iv)- संवैधानिक वैधता- उत्तराखंड राज्य सरकार की उक्त प्रावधान अधिनियमित करने की विधायी क्षमता –अभिनिर्धारित किया: किसी भी बाजार कानून का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कृषि के उत्पादक को उपज का उचित प्रतिफल मिलता है-धारा 27 (सी) (iii) इस अधिनियम की योजना के खिलाफ है, क्योंकि यह उन इकाइयों पर भी बाजार शुल्क और विकास उपकर लगाने का प्रयास करती है जो विनिर्माण करने के लिए केवल राज्य के बाहर से कृषि उत्पादों को बाजार क्षेत्र में लाती हैं- जिसमें कोई बाजार

क्षेत्र के भीतर उत्पाद की बिक्री या खरीद नहीं है- इसके अलावा, राज्य विधानमंडल के पास विवादित प्रावधानों को लागू करने के लिए क्षमता नहीं थी जो उन कृषि उत्पादों पर भी बाजार शुल्क और विकास उपकर को लागू करने की मांग करते थे, जिन को बाजार में बिक्री का उद्देश्य नहीं बल्कि निर्माण या आगे प्रसंस्करण के उद्देश्य से लाया जा रहा था- धारा 27 (सी) (iii) को निरस्त कर दिया गया है क्योंकि इसे राज्य विधानमंडल द्वारा ऐसा करने के लिए विधायी क्षमता के बिना अधिनियमित किया गया था-धारा 27 (ग) (iii) में संशोधन की वैधता को बनाए रखने का आदेश रद्द कर दिया गया है-परिणामतः अपीलार्थियों के खिलाफ बाजार शुल्क के भुगतान के लिए मांग की सूचना जारी करने और कोई अन्य आदेश पारित किए जानी की कार्रवाई को रद्द कर दिया-हालाँकि, धारा 27 (ग) (iv) का समर्थन किया जाता है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 उत्तराखंड कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2011 की प्रस्तावना से अवलोकन से पता चलता है कि यह अधिनियम उत्तराखंड राज्य में कृषि उपज विपणन को विनियमित करने और बाजारों का प्रभावी पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए के लिए बनाया गया है। प्रस्तावना अधिनियमन भाग को नियंत्रित नहीं कर सकती है। हालाँकि, अधिनियम के प्रावधानों के साथ पढ़ी जसने वाली प्रस्तावना,

विधायी योजना को स्पष्ट करती है और इसका अधिनियम के प्रावधानों के सही अर्थ निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है और अधिनियम के अन्य प्रावधानों को देखते हुए, क्या अधिनियम की संपूर्ण योजना को पराजित किए बिना अधिनियमन प्रावधान पर प्रभाव डाला जा सकता है। धारा 2 (i), 2 (ii), 2 (vi), 2 (xlvii), प्रावधानों और धारा 4 और प्रस्तावना के प्रावधान का एक संयुक्त पठन यह स्पष्ट करता है कि अधिनियम को अधिनियम की धारा 4 के तहत बाजार के रूप में अधिसूचित क्षेत्र के भीतर कृषि उपज खरीद और बिक्री को विनियमित करने के एक दृष्टिकोण के साथ अधिनियमित किया गया है। [पैरा 20,21 और 22] [323 जी-एच; 325-डी-ई; 327-ए-बी;]

1.2 किसी भी बाजार कानून का प्राथमिक उद्देश्य है यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कृषि उपज के उत्पादक को उचित प्रतिफल मिलता है। यह अनिवार्य रूप से "खरीदार-विक्रेता" संबंध को शासित करने के लिए भी है। धारा 27 (सी) (iii) की जाँच से पता चलेगा कि यह अधिनियम की योजना के खिलाफ है, क्योंकि यह उन इकाइयों पर भी बाजार शुल्क और विकास उपकर लगाने का प्रयास करता है जो केवल राज्य के बाहर से कृषि उपज को विनिर्माण करने के लिये बाजार क्षेत्र में लाती हैं, जिसमें बाजार क्षेत्र के भीतर उत्पाद की कोई बिक्री या खरीद नहीं है। [पैरा 24] [328-बी-डी]

1.3 सूची II की प्रविष्टि 28 बाजारों और मेलों से संबंधित है, जबकि सूची I की प्रविष्टि 52 उद्योग से संबंधित है। सूची I की प्रविष्टि 52 निर्माण और उत्पादन की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। इसलिए, तत्काल मामले में, राज्य विधानमंडल के पास उन विवादित प्रावधानों पर अधिनियम बनाने की क्षमता नहीं थी जो उन कृषि उपजों पर भी बाजार शुल्क और विकास उपकर लगाने की मांग करते थे जिन उत्पादों को बाजार में बिक्री के उद्देश्य से नहीं बल्कि निर्माण या आगे का प्रसंस्करण के उद्देश्य के लिए लाया जा रहा था। चूंकि राज्य विधानमंडल विवादित अधिनियम की धारा 27 (सी) (iii) के प्रावधान को अधिनियमित करने के लिए सक्षम नहीं था, इसलिये इसे रद्द किया जा सकता है क्योंकि क्योंकि इसे राज्य विधानमंडल द्वारा ऐसा करने के लिए विधायी क्षमता के बिना अधिनियमित किया गया था। [पैरा 25 और 26] [328-एफ; 330-एच; 331-ए-सी]

1.4 बिंदु संख्या 1 में अभिलिखित निष्कर्षों और कारणों को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 27 (ग) (iii) में संशोधन की वैधता को बनाए रखने वाले विवादित सामान्य निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अधिनियम की धारा 27 (ग) (iii) को निरस्त कर दिया जाता है। मांग की सूचना जारी करने की परिणामी कार्रवाई कोई अन्य पारित आदेश अपीलकर्ताओं के विरुद्ध मामला खारिज किया जाता है। हालांकि, धारा 27 (ग) (iii) को बरकरार रखा जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि क्रेता को यह साबित करना होगा कि कृषि उपज अन्य राज्य

से लाई जाती है जो एक अंतरराज्यीय बिक्री है, और माल की बिक्री अधिनियम 1930 के प्रावधानों के अनुसार है। [पैरा 27] [331-डी-ई]

भारत संघ बनाम एल्फिंस्टन कताई और बुनाई कं. लिमिटेड (2001) 4 एस. सी. सी. 139; 2001 (1) एससीआर 221 पर भरोसा किया।

आईटीसी लिमिटेड बनाम कृषि उपज बाजार समिति (2002) 9 एससीसी 232; 2002 (1) एस. सी. आर. 441; उड़ीसा राज्य बनाम एम. ए. टुलोच एंड कंपनी ए.आई.आर. 1964 एस सी सी 1284; 1964 एससीआर 461; द हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य 1961 एससीसी 459; टीका रामजी बनाम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1956 एस. सी. सी 676; 1956 एससीआर 393; महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय बनाम एम. पी. राज्य (2013) 15 एस. सी. सी. 677 : 2013 (13) एस. सी. आर. 464; विजयलक्ष्मी राइस मिल बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, पालोकल (2006) 6 एस. सी. सी. 763; 2006 (4) पूरक एस. सी. आर. 279; दिल्ली रेस क्लब लिमिटेड बनाम भारत संघ (2012) 8 एस. सी. सी. 680; 2012 (8) एससीआर 1; कवलाप्परा कोट्टाराथिल और कोचुन्नी उर्फ मूपिल नायर बनाम मद्रास और केरल राज्य 1960 एससी 1080; एम.सी.वी.एस. अरुणाचल नादर और अन्य बनाम मद्रास राज्य ए. आई. आर. 1959 एस. सी. सी. 300; 1959 पूरक एस. सी. आर. 92; द बेल्संड शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य

(1999) 9 एससीसी 620: 1999 (1) पूरक एस. सी. आर. 146-

संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

2002 (1) एससीआर 441	संदर्भित किया गया	पैरा 10
1964 एससीआर 461	संदर्भित किया गया	पैरा 12
1961 एससी 459:	संदर्भित किया गया।	पैरा 12
1956 एससीआर 393	संदर्भित किया गया।	पैरा 15
2013 (13) एससीआर 464	संदर्भित किया गया।	पैरा 16
2006 (4) पूरक। एससीआर 279	संदर्भित किया गया	पैरा 16
2012 (8) एससीआर 1	संदर्भित किया गया।	पैरा 17
ए.आर.आर 1960 एससीसी 1080	संदर्भित किया गया	पैरा 20
2001 (1) एससीआर 221	पर भरोसा किया गया	पैरा 20
1959 पूरक एस.सी.आर. 92	संदर्भित किया गया	पैरा 23
1999 (1) पूरक एस. सी. आर. 146	संदर्भित किया गया	पैरा 24

सिविल अपील न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं 14184-1418/2015

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, खंड पीठ, नैनीताल के 2014 की विशेष अपील सं. 384 और 2013 की विशेष अपील सं. 75 में दिनांकित 16.12.2014 निर्णय और आदेश से।

के साथ

2015 का सी. ए. सं. 14186-87, 14188-90, 14191-94, 14195, 14196-98, 14199-14209, 14210-14, 14215-16, 14217-18, 14219, 14220, 14221, 14222-34, 14235-37, 14238, 14239 40, 14241, 14242, 14243-46 और 14247

दुष्यंत दवे, अशोक के. परीजा, ए. के. गांगुली, डॉ. राजीव धवन, रमेश सिंह, पी. एस. सुधीर। ऋषि माहेश्वरी, ऐनी मैथ्यू, श्रुति जोस, राज कुमार कौशिक, पंकज कुमार सिंह, अनिरुद्ध पी. मयी, संजय कुमार विसेन, गौतम नारायण, आर. ए. अय्यर अपीलार्थियों की ओर से।

राहुल वर्मा एएजी, हरिन पी. रावल, अवतार सिंह रावत, राहुल वर्मा, सुदर्शन सिंह रावत, निपुण सक्सेना, आनंदो मुखर्जी, दिव्या आनंद, अंभोज कुमार सिन्हा, अनुव्रत शर्मा, रवि रंजन, शेखर कुमार, मुकेश कुमार। सिंह उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय **वी. गोपाल गौड़ा**, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था।

1. सभी विशेष अवकाश याचिकाओं में छूट दे दी गई।

2. वर्तमान अपीलें उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा अन्य विशेष अपीलों के एक समूह के साथ 2013 की विशेष अपील सं. 75 और 2014 की विशेष अपील सं.384 में पारित आम विवादित निर्णय और दिनांकित आदेश 16.12.2014 से उत्पन्न होती हैं जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2011 धारा 27 (ग) (iii) और 27 (ग) (iv) की वैधता को चुनौती को खारिज कर दिया और इसकी वैधता को बरकरार रखा।

3. पक्षों की ओर से आगे बढ़ाये गये प्रतिद्वंद्वी कानूनी विवाद के मामले के जिन संक्षिप्त तथ्यों की हमें सराहना करने की आवश्यकता है उनका उल्लेख नीचे किया गया है:

उत्तराखंड राज्य विधानमंडल ने उत्तराखंड कृषि उपज विपणन (विकास) और विनियमन) अधिनियम, 2011 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित), अधिनियमित किया जो 01.11.2011 पर लागू हुआ। अधिनियम की प्रस्तावना निम्नलिखितानुसार है:

"उत्तराखंड राज्य में कृषि उपज, स्थापना और विकास कृषि प्रसंस्करण और कृषि निर्यात, बाजारों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण और उससे संबंधित मामलों के लिए या आनुषंगिक विपणन में प्रभावी विनियमन के लिए एक अधिनियम।"

अधिनियम की धारा 27 (सी) (iii) में बाजार शुल्क और विकास उपकर लगाने का प्रावधान है, जो इस प्रकार है:

"ऐसी कोई भी कृषि उपज, बिक्री, भंडारण, प्रसंस्करण के लिए या किसी अन्य राज्य या देश के बाहर से लेन-देन जो राज्य क्षेत्र के किसी भी बाजार तक पहुँचती हो इसे पहली बार 'पहले आगमन' के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और ऐसी उपज पर, बाजार शुल्क और विकास उपकर देय होगा "

4. नतीजतन, "मंडी समितियों" अपीलार्थियों को नोटिस-सह-मांग ने पत्र भेजे। याचिकाकर्ताओं, जिन्होंने निर्माता होने का दावा किया, ने उच्च न्यायालय समक्ष रिट याचिका दायर की जिसमें मंडी समिति द्वारा उन उत्पादों पर जिन्हें अपीलार्थी बाजार क्षेत्र में लाए थे कृषि के लिए "बाजार शुल्क" के भुगतान करने के लिए की गई मांग को चुनौती दी। मुख्य चुनौती इस आधार पर रखी गई थी कि उनके कृषि उपज पर बाजार शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए कारण यह है कि, सबसे पहले, बाजार क्षेत्र में माल की कोई बिक्री और खरीद नहीं है और, दूसरा, धारा 27 (सी) (iii) के तहत इसका शुल्क इस कारण से नहीं लिया जा सकता है कि इस कृषि उपज कोई बिक्री, भंडारण, प्रसंस्करण या आदान-प्रदान नहीं है। उच्च न्यायालय

ने राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता को दी गई चुनौती को यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया कि:

"यहाँ का पिथ और पदार्थ उत्तराखंड का बाजार क्षेत्र होगा जो स्वीकार किया जाता है और वह प्रश्नगत उत्पाद एक कृषि उपज है। ये दोनों आवश्यक सामग्रियों को पूरा किया जा रहा है, विधायी क्षमता की अंतः चुनौती जीवित नहीं रहती है।"

उच्च न्यायालय ने माना कि अपीलार्थियों के तर्क का मुख्य जोर यह था कि बाजार शुल्क केवल तभी लिया जा सकता है जब कृषि उपज में बिक्री और खरीद शामिल है। और यहां तक कि जहां कृषि की कोई बिक्री और खरीद नहीं है उस घटना में "बाजार शुल्क" केवल तभी लिया जा सकता है जब माल केवल निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए खरीदा जाता है, जैसा कि अधिनियम की धारा 27 (सी) (iii) के तहत प्रदान किया गया है, अन्यथा नहीं। हालांकि, रिट याचिकाओं को इस हद तक अनुमति दी गई थी कि उनके खिलाफ मांग नोटिसों को इस टिप्पणी के साथ रद्द कर दिया गया कि अपीलकर्ता यहाँ बाजार में कृषि उपज को एक अनंतिम उत्पाद में निर्माण करने के लिये लाये थे। अपीलार्थियों का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन का भंडारण करना नहीं था बल्कि इसे दूसरे उत्पाद में परिवर्तित

करना था। इस प्रकार, उत्पाद का भंडारण केवल आकस्मिक उद्देश्यों के लिए था और इसके व्यवसाय के उद्देश्य लिए नहीं था।

5. इसके बाद, अधिसूचना दिनांक 03.01.2013 के माध्यम से, राज्य विधानमंडल ने उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम 2012 लागू किया। संशोधन अधिनियम की धारा 1 (2) यह प्रदान करती है कि उक्त अधिनियम 01.11.2011 से प्रभाव में आया माना जाएगा। अन्य प्रावधानों के अलावा, अधिनियम की धारा 27 (सी) (iii) में उक्त संशोधन द्वारा संशोधन किया गया था। संशोधित धारा 27 (सी) (iii) निम्नानुसार है:

"ऐसी कोई भी कृषि उपज, जो राज्य के किसी भी बाजार क्षेत्र में बिक्री, भंडारण, प्रसंस्करण, विनिर्माण, आदान-प्रदान और अन्य वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पहली बार किसी अन्य राज्य या देश से बाहर से आती हो तो उसे "प्राथमिक आगमन" के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और ऐसी उपज पर, बाजार शुल्क और विकास उपकर देय होगा।"

(इस न्यायालय द्वारा जोर दिया गया)

इसके बाद, अपीलार्थियों को कृषि उत्पादन मंडी समिति 'किच्चा'के कार्यालय के माध्यम से एक और नोटिस दिया गया, जिसके आधार पर उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि संशोधित अधिनियम,

2012 के अनुसार समिति के कार्यालय में मंडी शुल्क या विकास उपकर का भुगतान किया जाए।

6. पीड़ित, अपीलकर्ताओं ने संशोधन अधिनियम, 2012 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं। उच्च न्यायालय ने अपने 10.07.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश में कहा है कि पहले रिट याचिकाओं के समूह को एक सीमित बिंदु पर अनुमति दी गई थी कि राज्य विधानमंडल ने "निर्माण" शब्द को आरोपित अनुभाग में शामिल नहीं किया था, और हालांकि उसमें आक्षेपित संशोधन द्वारा इसमें, इस शब्द को पूर्वव्यापी रूप से जोड़ा गया था। इस प्रकार, वे आधार जो अपीलार्थियों के लिए पूर्व याचिका में उपलब्ध थे, अब यहाँ से आगे उपलब्ध नहीं थे। अधिनियम और नोटिस-सह-मांग की वैधता को बरकरार रखा गया।

7. उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित, अपीलकर्ताओं ने खंड पीठ के समक्ष विशेष अपील दायर की। डिवीजन बेंच ने अधिनियम के इन प्रावधानों की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलार्थी द्वारा दायर अपीलें योग्यता से रहित हैं। न्यायालय ने निम्नानुसार कहा कि;

"..... विवादित विधान में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि विधानमंडल ने बाजार क्षेत्र में अन्य बातों के साथ विनिर्माण

के उद्देश्य से लाए गए कृषि उत्पाद पर बाजार शुल्क/ उपकर लगाने का इरादा किया है।"

विधायी क्षमता के मुद्दे पर, प्रभाग पीठ ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"अन्य बातों के साथ-साथ निर्माण के उद्देश्य से कृषि उपज लाने का लेन-देन, बाजार शुल्क/उपकर का अधिरोपण आकर्षित करता है। हम सोचेंगे कि यह एक अलग करने योग्य लेन-देन है, जो अच्छी तरह से राज्य विधान-मंडल और उसके लिए प्रविष्टि 28, जिसे सूची। की प्रविष्टि 66 के साथ पढ़ा जाता है, उपलब्ध शक्तियों के दायरे के भीतर है। सूची। की प्रविष्टि 28 "बाजार" प्रदान करता है। बाजार में, हो सकता है, जो कि बिक्री और खरीद विनियमित करने का इरादा है; लेकिन, जैसा कि पहले से ही नोट किया गया है, बाजारों को विकसित और विनियमित किया जाना है।"

उच्च न्यायालय का दिनांक 10.07.2014 का विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया आदेश बरकरार रखा गया था। अतः वर्तमान में अपीलें।

8. हमने दोनों दलों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना है। हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिलेख पर तथ्यात्मक साक्ष्य के आधार पर,

मामले की परिस्थितियाँ और दोनों पक्षों के वरिष्ठ विद्वान वकीलों द्वारा आग्रह किए गए प्रतिद्वंद्वी कानूनी विवादों के आलोक में, हमने व्यापक रूप से निम्नलिखित बिंदु तैयार किये हैं जिन पर हमें ध्यान देने और विचार करने की आवश्यकता है:

1) क्या उत्तराखंड राज्य सरकार के पास आलोच्य प्रावधानों को अधिनियमित करने के लिए विधायी क्षमता है?

2) कौन सा आदेश?

बिन्दु 1 का उत्तर

9. श्री दुष्यंत दवे, अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि संशोधन संविधान के अधिकार से बाहर है, क्योंकि यह संविधान में प्रासंगिक प्रविष्टि के द्वारा समर्थित नहीं है। विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि तात्कालिक मामले में क्षेत्र को कवर करने वाली प्रासंगिक प्रविष्टि भारतीय संविधान की 7 वीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 28 है, जो निम्नानुसार है:

"28. बाजार और मेले"।

10. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आईटीसी लिमिटेड बनाम कृषि उपज बाजार समिति के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय पर भरोसा किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

"128. यदि 'उद्योग' में 'बाजार और मेले' शामिल नहीं हैं तो यह परिभाषित करना महत्वपूर्ण है कि बाजार और मेलों का क्या अर्थ है। 'बाजार' को सख्त रूप में "एक निश्चित समय और स्थान पर वस्तुओं या पशुधन की खरीद- बिक्री के लिये बैठक या लोगों को एक साथ इकट्ठा करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक 'मेला' को न्यायिक रूप से कभी-कभी या प्रथा द्वारा निर्धारित..... सामान्यतया क्रय-विक्रय के स्थान पर 'खरीदारों और विक्रेताओं का एक आवधिक समूह' के अर्थ के रूप में परिभाषित किया गया है। बाजारों और मेलों के बीच में यह अंतर आवधिकता में निहित प्रतीत होता है अर्थात् जबकि एक बाजार नियमित या व्यापार का स्थायी स्थान हो सकता है; मेला एक रुक-रुक कर चलने वाला है। आम कानून में, मेले और बाजार भी फ्रेंचाइजी या उन वस्तुओं का निपटान करने के जिनके संबंध में फ्रेंचाइजी को दिया जाता है खरीदारों और विक्रेताओं का एक समूह रखने का अधिकार थे। इसमें बाजार में वस्तुओं की बिक्री पर खरीदार द्वारा देय टोल या धनराशि लगाने का अधिकार शामिल था। जिस अर्थ में प्रविष्टि 28 में शब्दों का उपयोग किया गया है वह न केवल इस अधिकार को शामिल किया गया है, बल्कि खरीदारों

और विक्रेताओं के समूह सहित स्वयं बाजार स्थान और इन सभी का विनियमन भी शामिल है।”

विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि इसका मतलब है कि प्रविष्टि 28 के तहत, कानून बनाने की शक्ति में अधिनियम में सहायक शक्तियों पर कानून बनाना शामिल है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे अधिनियम की प्रस्तावना पर निर्भरता रखी है जिसे निर्णय के पूर्व भाग में उद्धृत किया गया है।

11. विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य किसान की रक्षा करना और यह देखना है कि कृषि उपज या तो बाजार क्षेत्र या बाजार यार्ड में बेची जाती है। इसके अलावा, अधिनियम में जो विचार किया गया है वह केवल राज्य में शामिल माल बिक्री है और उस माल की बिक्री नहीं जो राज्य के बाहर होता है।

12. विधायी क्षमता के मुद्दे पर, विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि राज्य ने भारतीय संविधान सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 28, जिसे सूची II की प्रविष्टि 66 के साथ पढ़ा जाता है के दायरे से परे जाकर संशोधन अधिनियम में उपरोक्त आक्षेपित प्रावधानों को लागू करते समय अपने विधान क्षमता को पार कर लिया है। इससे भी अधिक, जब संसद द्वारा बनाया गया एक कानून, अर्थात्, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 पहले से ही इस मामले में एकाधिकार रखता है। विद्वान

वरिष्ठ वकील ने उपरोक्त आई. टी. सी. लिमिटेड के मामले में निर्णय के निम्नलिखित पैराग्राफ पर भरोसा किया:

"110. इस मामले में तीन विधायी सूचियों में प्रयुक्त "उद्योग" शब्दों के अर्थ पर विवाद काफी हद तक बदल जाता है। अब सूची। की प्रविष्टि 7 और 52 के अधीन सूची।। की प्रविष्टि 24 के तहत सभी उद्योगों के मामले में कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडलों को दी गई है। सूची। की प्रविष्टियाँ 7 और 52 संसद को विशेष 'उद्योगों' के संबंध में कानून बनाने की अनुमति देती हैं- अर्थात् ऐसे उद्योग जो संसद द्वारा कानून द्वारा डिफेंस या युद्ध अभियोजन के लिए आवश्यक घोषित किए जाते हैं (प्रविष्टि 7) और ऐसे उद्योग जिनका नियंत्रण संसद द्वारा कानून द्वारा संघ को समीचीन जनहित में (प्रविष्टि 52) में व्यापार और वाणिज्य घोषित किया गया है। व्यापार और वाणिज्य और ऐसे नियंत्रित उद्योग के उत्पादों की उत्पादन आपूर्ति और वितरण को समवर्ती सूची प्रविष्टि 33 में प्रदान किया गया है, जिसमें संसद और राज्य विधानमंडल कानून बनाने के लिए सक्षम हैं। कलकत्ता गैस कंपनी (प्रो.) लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने माना है कि तीनों सूचियों में उद्योग शब्द का एक ही अर्थ दिया जाए

और जबकि सामान्य रूप से उद्योग राज्य विधान के क्षेत्र में है, सूची॥ में अन्य प्रविष्टियों के संदर्भ में इस तरह से समझा जाए कि सूची॥ में कोई भी प्रविष्टि इसकी सामग्री से वंचित न रहे। दूसरे शब्दों में, 'उद्योग' शब्द का अर्थ सूची॥ की प्रविष्टि 24 के संदर्भ में निर्धारित किया जाना है जहाँ उद्योगों के संबंध में आम तौर पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रविष्टियाँ 7 और 52 वह प्रविष्टियाँ हैं जो इनमें सामान्य पूल से विशेष उद्योगों को निर्दिष्ट करती हैं। इन दोनों प्रविष्टियों में 'उद्योग' शब्द का अर्थ अनिवार्य रूप से उस अर्थ के प्राप्त किया जाना चाहिए जो सूची॥ की प्रविष्टि 24 में शब्द से जोड़ा जा सकता है।"

126. संक्षेप में: सूची॥ की प्रविष्टि 52 के उद्देश्यों के लिए 'उद्योग' शब्द को टीका रामजी द्वारा दृढ़ता से केवल निर्माण या उत्पादन की प्रक्रिया के लिए सीमित किया गया है। अन्य संविधान पीठों सहित बाद के बाद के निर्णयों ने इस बात की फिर से पुष्टि की है कि टीका रामजी मामला आधिकारिक रूप से 'उद्योग' शब्द को परिभाषित करता है-जिसका अर्थ है निर्माण या उत्पादन की प्रक्रिया और जो उद्योग में उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल या उद्योग के उत्पादों का वितरण शामिल नहीं करता है। संवैधानिक ढांचा और न्यायपालिका प्राधिकरण के महत्व को देखते हुए उद्योग शब्द के व्यापक अर्थ को प्रचारित करने वाले तर्क को स्वीकार करना

संभव नहीं है। किसी अन्य संदर्भ में इस शब्द का जो भी अर्थ हो, उसे संवैधानिक संदर्भ में ' निर्माण या उत्पादन ' के अर्थ के रूप में समझा जाए।

विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रतिकूलता अवधारणा पर विस्तार से चर्चा करने के लिए उड़ीसा राज्य बनाम एम. ए. टुलोच एंड कंपनी के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा जो निम्नानुसार है :

“..... आलोच्यता तब उत्पन्न होती है जब दो अधिनियम दोनों दो विधानमंडलों की क्षमता के भीतर टकराते हैं और जब संविधान स्पष्ट रूप से या आवश्यक रूप से निहितार्थ प्रदान करता है कि एक विधायिका का अधिनियमन को दूसरे पर श्रेष्ठता प्राप्त है तब उस आलोच्यता की सीमा तक एक विधानमंडल दूसरे की जगह लेता है। लेकिन दो अधिनियम एक-दूसरे के लिए प्रतिकूल हो सकते हैं, भले ही उनमें से प्रत्येक की आज्ञाकारिता दूसरे की अवज्ञा के बिना संभव है। दो विधानों का परीक्षण हालाँकि, प्रतिकूलता का मानदंड नहीं है, क्योंकि यदि एक सक्षम विधानमंडल एक बेहतर प्रभावकारिता के साथ स्पष्ट रूप से या निहित रूप से अपने विधान द्वारा पूरे क्षेत्र को शामिल करने का इरादा रखती है, दूसरी तो अन्य विधायिका के अधिनियम चाहे

पारित किए गए हों इससे पहले या बाद में आलोच्यता के आधार पर अतिरंजित किया जायेगा। जहाँ ऐसी स्थिति है, विसंगति दोनों कानूनों के प्रावधानों का विस्तृत संपीड़न द्वारा नहीं बल्कि केवल दो विधियों के दोनों हिस्सों के अस्तित्व मात्र से प्रदर्शित होती है.....।"

विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे द हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड बनाम उडीसा राज्य के मामले पर भरोसा रखा जिसके प्रासंगिक भाग को नीचे उद्धृत किया गया है:

"..... इस प्रश्न से निपटने से पहले कर और शुल्क की अवधारणा के बीच के अंतर पर विचार करना आवश्यक है। मैथ्यू बनाम चिकोरी विपणन बोर्ड (1938) 60 सी. एल. आर. 263 में लैथम, सी. जे. द्वारा दी गई कर की साफ और संक्षिप्त परिभाषा को अक्सर इस विषय पर एक क्लासिक के रूप में उद्धृत किया जाता है।"। लैथम, सी. जे. ने कहा, "एक कर" कानून द्वारा प्रवर्तनीय सार्वजनिक उद्देश्य के लिये सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा धन का अनिवार्य निष्पादन है, और प्रदान की गई सेवाओं के लिए, भुगतान नहीं है"। कर की आवश्यक विशेषताओं को बाहर लाने में यह परिभाषा शुल्क से कर को अलग करने में भी सहायता

करती हैं। यह सच है कि कर और शुल्क में कोई सामान्य अंतर नहीं है। दोनों सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा धन का अनिवार्य निष्पादन हैं; लेकिन जबकि एक कर सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए लगाया जाता है और बदले में प्रदान की गई सेवा के किसी भी विचार द्वारा समर्थित होने की आवश्यकता नहीं है, जबकि बदले में दी गई सेवा के लिए अनिवार्य रूप से शुल्क लगाया जाता है और इस तरह शुल्क का भुगतान करने वाले व्यक्ति और सार्वजनिक प्राधिकरण जो इसे लागू करता है दोनों के बीच इस तरह का एक तत्व है। यदि एक विशिष्ट क्षेत्र या किसी स्थानीय क्षेत्र में व्यक्ति या व्यापार या व्यवसाय के एक विशिष्ट वर्ग के लिए विशिष्ट सेवाएँ प्रस्तुत की जाती हैं, और कथित सेवाओं के लिए या बदले में पूर्ववर्ती शर्तस्वरूप उक्त क्षेत्र या उक्त क्षेत्र के व्यक्तियों या व्यापारिक या व्यवसायिक वर्ग पर उपकर लगाया जाता है उपकर एक कर से अलग है और एक शुल्क के रूप में वर्णित है। सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा पुनर्प्राप्त कर हमेशा समेकित निधि में जाता है जिसका उपयोग अंततः सभी जनता के उद्देश्यों के लिए लिए किया जाता है, जबकि शुल्क के रूप में लगाया गया उपकर एक समेकित निधि का हिस्सा बनने के इरादे से नहीं होता है, और नहीं बनता है।

यह उन सेवाओं के उद्देश्य के लिये निर्धारित किया जाता है और इसके लिए अलग रखा गया है जिनके लिए यह लगाया जाता है। हालाँकि, कर और शुल्क दोनों के अधिरोपण में मजबूरी का एक तत्व होता है। जब विधानमंडल किसी क्षेत्र या व्यक्तियों के किसी वर्ग के लिए कोई विशिष्ट सेवा प्रदान करने का निर्णय लेता है, तो यह उक्त क्षेत्र या उक्त वर्ग के व्यक्तियों लिए यह निवेदन करना खुला नहीं है कि वे सेवा नहीं चाहते हैं और इसलिए उन्हें सेस भुगतान से छूट दी जानी चाहिए। हालाँकि कर दाता और सार्वजनिक प्राधिकरण के बीच क्विड प्रो क्वो का एक तत्व है सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सेवा प्राप्त करने के मामले में करदाता के लिए कोई विकल्प नहीं है। शुल्क के संबंध में, एकत्र किया गया शुल्क और प्रदान की जाने वाली सेवा के बीच सह-संबंध है, और हमेशा होना चाहिए। जहां शुल्क छोड़ने की आड़ में मामले सामने आ सकते हैं विधायिका कर लगाने का प्रयास कर सकती है; और विधायी शक्ति के इस तरह के एक रंगीन अभ्यास के मामले में न्यायालयों को लेवी की योजनाओं की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी और यह निर्धारित करना होगा कि क्या वास्तव में सेवा और शुल्क के बीच कोई सह संबंध है, या क्या शुल्क या तो सेवा

के साथ सह-संबंधित नहीं है या इसके लिए ऐसी अत्यधिक सीमा तक लगाया जाता है जो शुल्क का ढोंग हो और वास्तव में कोई शुल्क नहीं। दूसरे शब्दों में, एक कानून द्वारा जीवित विशेष उपकर एक शुल्क या कर के बराबर होता है या नहीं यह हमेशा एक तथ्य का प्रश्न होगा जिसे प्रत्येक मामले की परिस्थितियों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। हालांकि, एक कर और एक शुल्क के बीच अंतर महत्वपूर्ण है, और यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। तीन सूचियों में कई प्रविष्टियाँ उपयुक्त विधानमंडलों को कर लगाने के लिए सशक्त बनाती हैं; लेकिन इस प्रकार प्रदत्त करों को लगाने की शक्ति के अलावा प्रत्येक सूची विशेष रूप से उक्त सूची में शामिल संबंधित शुल्क लगाने की शक्ति को संदर्भित करती है।"

विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि शुल्क के वैध अधिरोपण के लिए विधायी योग्यता एक पूर्व शर्त है।

13. श्री अशोक के. परीजा, कुछ अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि 2012 का संशोधन अधिनियम संवैधानिक रूप से मान्य नहीं है क्योंकि राज्य विधायिका के पास उत्पादन गतिविधियों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। उनका तर्क है कि

निर्माण के बाद, उत्पाद कृषि उपज बनना बंद कर देता है। इस प्रकार, औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम, 1951 का कानून अस्तित्व में है।

14. दूसरी ओर, श्री अवतार सिंह रावत, उत्तराखंड राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता अधिनियम की योजना का उल्लेख करते हुए तर्क देते हैं कि अधिनियम का उद्देश्य कुशल विपणन प्रणालियाँ विकसित करना है। तत्काल मामले में में प्रासंगिक प्रविष्टि सूची॥ की प्रविष्टि 28 अस्तित्व में है।

15. श्री हरिन पी. रावल, मंडी समितियों की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील आगे तर्क देते हैं कि उत्तराखंड के राज्य विधानमंडल के पास विवादित प्रावधानों को अधिनियमित करने की क्षमता थी। वह तर्क देते हैं कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची। की प्रविष्टि 28, जो "बाजार और मेलों" से संबंधित है, राज्य विधानमंडल में बाजार और मेलों के संचालन या उनकी वृद्धि और विकास विनियमन करने वाला कोई भी प्रावधान करने की अनन्य रूप से शक्ति निहित करती है। आगे सूची॥ की प्रविष्टि 66 राज्य सरकार को इस सूची में मामले इनमें से किसी के भी संबंध में शुल्क लगाने की शक्ति प्रदान करती है "। यहाँ विवादित विधान किया गया है राज्य विधानमंडल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया है, और इसलिए बाजार शुल्क और इसके अनुसरण में विकास उपकर पूरी तरह से राज्य विधानमंडल की विधायी

क्षमता के अंतर्गत आता है। विद्वान वरिष्ठ वकील आगे तर्क देते हैं कि यह तथ्य, कि कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पाद का उपयोग सूची। की प्रविष्टि 52 द्वारा कवर एक उद्योग द्वारा किया जाता है राज्य विधानमंडल को लेन-देन के संबंध में बाजार शुल्क या उपकर लगाने की शक्ति के अधिकार से वंचित नहीं करती है, जो अच्छी तरह से राज्य विधानमंडल के दायरे के भीतर है। कृषि उपज को बाजार क्षेत्र में लाना बाजार शुल्क/उपकर को आकर्षित करता है जिसे लागू करने के लिए राज्य विधानमंडल सक्षम है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने टीका रामजी बनाम यू. पी. राज्य के मामले पर भरोसा रखा; जिसमें सूची। की प्रविष्टि 52 के उद्देश्य के लिए 'उद्योग' शब्द का दायरा निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया था:

"व्यापक अर्थों में उद्योग तीन अलग-अलग पहलुओं को शामिल करने में सक्षम होगा: (1) कच्चा माल जो औद्योगिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, (2) निर्माण या उत्पादन की प्रक्रिया, और (3) उद्योग के उत्पादों का वितरण। कच्चा माल ऐसी वस्तुएँ होंगी जो सूची। की प्रविष्टि 27 में शामिल होंगी। निर्माण की प्रक्रिया या उत्पादन को सूची। की प्रविष्टि 24 में शामिल किया जाएगा सिवाय इसके कि उद्योग एक नियंत्रित उद्योग था जब यह सूची। की प्रविष्टि 52 और इसके उत्पादों के अंतर्गत आएगा उद्योग को सूची। की प्रविष्टि 27 में भी शामिल किया

जाएगा वहाँ को छोड़कर जहाँ वे नियंत्रित उद्योग के उत्पाद थे जब वे सूची।।। की प्रविष्टि 33 के अंतर्गत आते हैं।"

16. विद्वान वरिष्ठ वकील आगे तर्क देते हैं कि अपीलार्थियों द्वारा अधिनियम की प्रस्तावना पर निर्भरता गलत है क्योंकि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि जब कानून के प्रावधान स्पष्ट और त्रुटिरहित हैं, तो प्रस्तावना को अनिवार्य रूप से महत्वहीन होना चाहिए। विधान के प्रावधानों में अस्पष्टता के मामले में प्रस्तावना का उपयोग विधानमंडल के मन को खोलने के लिए एक कुंजी के रूप में किया जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय बनाम. एम. पी. राज्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें पैरा 87 पर, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार यह माना गया था:

"बहुत शुरुआत में, यह माना जाना चाहिए कि प्रस्तावना अधिनियम की प्रयोज्यता के दायरे को नियंत्रित नहीं कर सकती है। यदि मुख्य अधिनियम में निहित प्रावधान स्पष्ट और बिना किसी अस्पष्टता हैं और इस प्रकार विधान उद्देश्य को बिना किसी प्रयास के विधिवत समझा जा सकता है, तो यहाँ तक कि उस उद्देश्य के लिए प्रस्तावना को देखने की भी आवश्यकता नहीं है।"

विद्वान वरिष्ठ वकील आगे तर्क देते हैं कि तत्काल मामले में लगाया जाने वाला विकासात्मक उपकर शुल्क है, जिसे लगाने की शक्ति प्रविष्टि 66 सहपठित सूची॥ की प्रविष्टि 28 के तहत राज्य विधानमंडल को प्रदान की गई है। आगे तर्क दिया गया है कि संविधान कृषि उपज की बिक्री पर या इसके बिना भी बिक्री के, बाजार क्षेत्र में किसी भी कृषि उपज को लाने पर, चाहे वह प्रसंस्करण के लिए हो या विनिर्माण के लिए शुल्क लगाने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने विजयलक्ष्मी राईस मिल बनाम व्यापारिक कर पालोकल मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें निम्नलिखित शब्दों में 'उपकर' और 'शुल्क' के बीच एक अंतर बनाने की कोशिश की गई थी :

".....इसलिए आम तौर पर एक उपकर भी एक कर है, लेकिन एक विशेष प्रकार का कर है। आम तौर पर कर राजस्व बढ़ाता है जो हो सकता है कि राज्य द्वारा आम तौर पर किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, आयकर या उत्पाद शुल्क या बिक्री कर ऐसे कर हैं जो राजस्व उत्पन्न करते हैं जिसका उपयोग केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, उदाहरण के लिए सशस्त्र बलों के सदस्यों या सिविल सेवक पुलिस आदि को वेतन, या विकास कार्यक्रमों के लिए,आदि। हालांकि, उपकर एक ऐसा कर है जो राजस्व

उत्पन्न करता है जिसका उपयोग एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य उपकरण से राजस्व बढ़ता है जिसका उपयोग स्वास्थ्य के लिए किया जाता है जैसे अस्पतालों का निर्माण, गरीब लोगों को दवाएं देना आदि। इसी तरह शिक्षा उपकरण से राजस्व में वृद्धि होती है इसका उपयोग विद्यालयों के निर्माण या अन्य शैक्षिक कार्यों के उद्देश्य के लिए किया जाता है.....

यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक कर और एक शुल्क के बीच बुनियादी अंतर यह है कि एक कर सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए एक राज्य या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा धन का एक अनिवार्य निष्पादन है, और यह कुछ विशिष्ट सेवाओं के लिए एक भुगतान नहीं है। दूसरी तरफ, एक शुल्क को आम तौर पर किसी सरकारी एजेंसी द्वारा प्रदान की गई एक विशेष सेवा के शुल्क के रूप में परिभाषित किया जाता है।"

17. विद्वान वरिष्ठ वकील आगे तर्क देते हैं कि शुल्क और सेस लगाने के लिए क्विड प्रो क्वो एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में, दिल्ली रेस क्लब लिमिटेड बनाम भारत संघ ' मामले पर निर्भरता रखी गई है, जिसमें निम्नानुसार यह माना गया था कि:

"सिकंदराबाद हैदराबाद होटल ओनर्स एसोसिएशन मामले (ऊपर) में भी यही सिद्धांत दोहराया गया था जहाँ दो प्रकार के शुल्क और उनके बीच अंतर का अस्तित्व पर निम्नानुसार प्रकाश डाला गया है: "9. यह, अब तक, अच्छी तरह से तय किया जा चुका है कि एक लाइसेंस शुल्क या तो नियामक या प्रतिपूरक हो सकता है। जब शुल्क विशिष्ट सेवाएँ प्रदान करने के लिये लिया जाता है, तो प्रदत्त सेवा और वसूली गई शुल्क के बीच क्विड प्रो क्वो का एक निश्चित तत्व होना चाहिए ताकि लाइसेंस शुल्क सेवा प्रदान करने की लागत के अनुरूप हो हालांकि सटीक अंकगणितीय समतुल्यता अपेक्षित नहीं है। हालांकि, यह एकमात्र प्रकार का शुल्क नहीं है जो लिया जा सकता है। लाइसेंस शुल्क भी नियामक हो सकता है जब ऐसी गतिविधियाँ जिनके लिए लाइसेंस दिया जाता है उनको विनियमित या नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। ऐसी गतिविधि के लिए विनियमन के लिए लिया जाने वाला शुल्क वैध रूप से एक शुल्क के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और कर के रूप में नहीं, हालांकि कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है। इस तरह के शुल्क लगाने के लिए क्विड प्रो क्वो का एक तत्व होने

की आवश्यकता नहीं है, हालांकि इस तरह के शुल्क की अति नहीं हो सकती।"

18. विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि शुल्क जो तत्काल मामले में लगाए जाने की मांग की जाती है, बाजार क्षेत्र का विकास के लिए है और इसलिए भले ही अपीलार्थी इससे सीधे लाभान्वित नहीं होते हैं, शुल्क के अधिरोपण को निरर्थक नहीं माना जा सकता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि तत्काल मामले में जो जांच करने की आवश्यकता है वह है उपकरण की घटना का बिंदु। घटना का बिंदु है, सबसे पहले कृषि उपज को बाजार क्षेत्र में लाया जाना और दूसरा, किसी भी कृषि उत्पादन की खरीद या बिक्री। वह प्रस्तुत करते हैं कि विवादित प्रावधान संवैधानिक रूप से वैध हैं और इस प्रकार, निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

19. दोनों पक्षकारों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील को सुनने के बाद, हम श्री अवतार सिंह, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, और श्री हरिन पी. रावल, उत्तरदाताओं से की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों से सहमत होने में असमर्थ हैं।

20. अधिनियम की प्रस्तावना के अवलोकन से पता चलता है कि अधिनियम उत्तराखंड राज्य में कृषि उत्पाद के विपणन को विनियमित और बाजार के प्रभावी अधीक्षण और नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है। इस

स्तर पर, वैधानिक व्याख्या की सहायता के रूप में प्रस्तावना की भूमिका की जांच करना अनिवार्य है।

कवलाप्पारा कोट्टाराथिल और कोचुन्नी उर्फ मूपिल नायर बनाम मद्रास और केरल राज्यों के मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा निम्नानुसार माना गया:

"कानून की प्रस्तावना "समझ की एक कुंजी" है और यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जब भी अधिनियमित करने वाला भाग इनमें से किसी भी मामले में संदेह के लिए खुला है तब इसका किसी भी अस्पष्टता को हल करने के लिए, या जिन शब्दों में एक से अधिक हो सकते हैं उनके अर्थ को ठीक करने के लिए या अधिनियम का प्रभाव उसके वास्तविक दायरे में रखने के लिए वैध रूप से परामर्श लिया जा सकता है"

हाल ही में, इस न्यायालय की एक और संविधान पीठ ने एल्फिंस्टन स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड, मामले ठीक इसी से निपटा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार यह माना गया:

" जब एक एक कानून में कुछ प्रावधान के अर्थ के बारे में सवाल उठता है तो उस प्रावधान को उसके संदर्भ में पढ़ना न केवल वैध है बल्कि उचित भी है। संदर्भ का अर्थ है;

समग्र रूप से कानून, कानून की पिछली स्थिति, पैरा मैटेरिया में अन्य कानून, कानून का सामान्य दायरा और शरारत जिसे सुधारने का इरादा था। एक अधिनियम में एक लंबा शीर्षक होता है जो प्रस्तावना से पहले होता है और उक्त लंबा शीर्षक स्वयं एक अधिनियम का हिस्सा है और इसके निर्माण में सहायता के रूप में स्वीकार्य है। कई मामलों में यह माना गया था कि एक लंबा शीर्षक प्रस्तावना के साथ या इसकी अनुपस्थिति में भी अधिनियम के उद्देश्य, दायरे या उद्देश्य के बारे में एक अच्छा मार्गदर्शक है जबकि प्रस्तावना संदर्भ के उद्देश्य के लिये केवल एक संक्षिप्त नाम है और निर्माण के लिए उपयोगी सहायता नहीं हैं। एक अधिनियम की प्रस्तावना, इसमें कोई संदेह नहीं है, कि अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ में अधिनियमित प्रावधानों को लागू करने में शब्द के अर्थ का पता लगाने के लिए यह तय करने के लिए कि क्या वे स्पष्ट या अस्पष्ट हैं पढ़ी जा सकती है लेकिन प्रस्तावना एक अधिनियमित प्रावधान नहीं होने के नाते अधिनियम के एक खंड के निर्माण में एक सहायता के रूप में अपने आप में समान वजन की नहीं है जैसा कि अधिनियम में दूसरी जगह पाये जाने वाले सम्बंधित अधिनियम शब्द रखते हैं।

अधिनियमित प्रावधानों को लागू करने की स्पष्टता के बारे में किसी निष्कर्ष पर प्रस्तावना की उपयोगिता कम हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रस्तावना अन्यथा अधिनियमित करने वाले भागों के अर्थ को प्रभावित करने के लिये उत्तरदायी नहीं है जब तक कि वहाँ इसे मजबूर करने का एक ठोस कारण है।"

(इस न्यायालय द्वारा जोर दिया गया)

21. उपर्युक्त कानून के अवलोकन से, यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तावना अधिनियमन भाग को नियंत्रित नहीं कर सकती है। किसी कानून के प्रावधानों के साथ पढ़ी जाने वाली प्रस्तावना, हालाँकि, विधायी योजना को स्पष्ट करती है और इसका उपयोग अधिनियमित करने वाले प्रावधान का सही अर्थ निर्धारित करने के लिये किया जा सकता है और चाहे अधिनियम के अन्य प्रावधानों को देखते हुए, पूरे अधिनियम योजना को विफल किए बिना अधिनियमन प्रावधान को प्रभावी बनाया जा सकता है। अधिनियम की योजना को पूरी तरह से समझने के लिए, हमें कुछ प्रावधानों पर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

धारा 2 (i) "कृषि उपज" को इस प्रकार परिभाषित करती है:

"कृषि उपज" का अर्थ है सभी उपज और वस्तुएँ, चाहे संसाधित हों या असंसाधित, कृषि, बागवानी, फूलों की

खेती, विटिकल्चर, एपिकल्चर, सीरीकल्चर, फिस्सिकल्चर, पशु पालन, वनोत्पाद, जैसा अनुसूची में निर्दिष्ट या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा घोषित उत्पाद और दो या दो से अधिक उत्पादों का मिश्रण रूप में प्रसंस्कारित और आगे इसमें गुड रब, शक्कर, खंडसरी और गुड भी शामिल है।

धारा 2 (ii) एक 'कृषक' या 'उत्पादक' को इस प्रकार परिभाषित करती है:

"कृषक "या" उत्पादक " ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है, जो- अपने श्रम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के श्रम से या भाड़े के श्रम से या अन्यथा, कृषि के उत्पादन और विकास में लगे हुए उत्पादन करता है है, लेकिन इसमें बाजार का कोई भी पदाधिकारी जैसे एक व्यापारी, दलाल (दलाल), कमीशन एजेंट या आढ़तिया जो अन्यथा सामान्य रूप से कृषि उपज का भंडारण व्यवसाय में लगा हुआ है, शामिल नहीं है;"

धारा 2 (vi) "खरीदार" को इस प्रकार परिभाषित करती है:

"क्रेता (खरीदार) का अर्थ है एक व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, फर्म या कंपनी या सहकारी समिति या सरकारी एजेंसी,

निगम, व्यापारी, कमीशन एजेंट या आढ़तिया, जो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति या अभिकर्ता की ओर से, इस अधिनियम के तहत अधिसूचित बाजार क्षेत्र में कृषि उपज खरीदता है या खरीदने के लिए सहमत होता है;

धारा 2 (xlvi) "दूसरे आगमन" को इस प्रकार परिभाषित करती है।

"द्वितीय आगमन का अर्थ है ऐसी कृषि उपज, जिसे किसी अन्य बाजार क्षेत्र से पहले लेन-देन या बिक्री के बाद किसी भी बाजार क्षेत्र में लाया गया है;"

अधिनियम की धारा 4 किसी क्षेत्र की बाजार क्षेत्र के रूप में घोषणा से संबंधित है जो नीचे लिखा है:

"जहाँ राज्य सरकार की यह राय है कि लोक हित में किसी भी क्षेत्र में कृषि उपज की बिक्री और खरीद को विनियमित करने के लिए और उस उद्देश्य के लिए उस क्षेत्र को बाजार क्षेत्र घोषित करना आवश्यक या समीचीन है, वह, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना और इस तरह का अन्य तरीका, जो विहित किया जाए, के द्वारा उस क्षेत्र को ऐसी तिथि, जिसे अधिसूचित किया जाए, से प्रभावी, इस

अधिनियम के तहत एक बाजार क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकती है”

22. उपर्युक्त सभी प्रावधान और प्रस्तावना का एक संयुक्त पठन यह स्पष्ट करता है कि अधिनियम अधिनियम की धारा 4 के तहत क्षेत्र को बाजार के रूप में अधिसूचित क्षेत्र के भीतर कृषि उपज का क्रय और विक्रय को विनियमित करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया है।

पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम आक्षेपित प्रावधान, अर्थात् धारा 27 (ग) (iii) को निकालते हैं :

“ऐसी कोई भी कृषि उपज, जो बिक्री, भंडारण, प्रसंस्करण, विनिर्माण, लेन-देन या अन्य वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए राज्य के किसी भी बाजार क्षेत्र में पहली बार किसी अन्य राज्य या देश से बाहर से आती हो, इसे “प्राथमिक आगमन” के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और इस प्रकार की उपज पर, बाजार शुल्क और विकास उपकर देय होगा।”

धारा 27 (ग) (iv) इस प्रकार है:

ऐसी कोई भी कृषि उपज जो भंडारण, प्रसंस्करण, विनिर्माण, लेनदेन या अन्य वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए देय बाजार शुल्क और विकास उपकर के भुगतान के बाद राज्य के किसी अन्य बाजार क्षेत्र से राज्य के भीतर बिक्री के लेन-देन के बाद बाजार क्षेत्र में लायी जाती है तो, इसे

"माध्यमिक आगमन" कहा जाएगा और ऐसी उपज पर कोई बाजार शुल्क नहीं और विकास उपकर देय होगा।

23. इससे पहले कि हम राज्य विधानमंडल की विवादित प्रावधानों को अधिनियमित करने के लिए विधायी क्षमता की जांच करें, हम इस न्यायालय एक संविधान पीठ के निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करें जो, M.C.V.S नादर और अन्य बनाम मद्रास राज्य के मामले में प्रस्तुत किया गया जिसमें सामान्य रूप से बाजार कानूनों का मूल्यांकन किया गया था:

".....विपणन कानून अब सभी वाणिज्यिक देशों में एक सुव्यवस्थित विशेषता है। इस तरह के कानून का उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों के उत्पादकों की बिचौलियों और मुनाफाखोरों द्वारा शोषण किये जाने से रक्षा करना है और उन्हें अपनी उपज के लिए उचित लाभ सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है।"

24. इस प्रकार, किसी भी बाजार कानून का प्राथमिक उद्देश्य है- यह सुनिश्चित करना कि कृषि उपज के उत्पादक को एक उचित प्रतिफल मिले। यह अनिवार्य रूप से खरीदार विक्रेता के संबंध को नियंत्रित करने के लिए भी है।

इस संदर्भ में, धारा 27 (सी) (iii) की जांच यह प्रदर्शित करती है कि यह अधिनियम की योजना के खिलाफ है, क्योंकि यह उन इकाइयों पर भी बाजार शुल्क और विकास उपकर लगाना चाहता है जो केवल विनिर्माण करने के लिए बाजार क्षेत्र में राज्य के बाहर से कृषि उपज लाते हैं, जिसमें स्वयं में बाजार क्षेत्र के भीतर उत्पाद की कोई बिक्री या खरीद नहीं है।

25. इसके अलावा, विशेष प्रावधान अधिनियमित करने के लिए राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता की जांच करना महत्वपूर्ण है। यहाँ मैदान में दो प्रासंगिक प्रविष्टियाँ हैं सूची। की प्रविष्टि 52 और सूची॥ की प्रविष्टि 28।

सूची॥ की प्रविष्टि 28 बाजारों और मेलों से संबंधित है, जबकि सूची। की प्रविष्टि 52 उद्योग से संबंधित है। द बेलसुंड शुगर कं. लिमिटेड बनाम बिहार राज्य के मामले में अन्य बातों के साथ निम्नानुसार माना गया था:

“यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि यदि बाजारों का स्थान और मेलों का सरलीकरण और प्रबंधन और इसके रखरखाव पर केवल बाजार अधिनियम द्वारा विचार किया जाता है, तो वे स्पष्ट रूप से सूची 1 की प्रविष्टि 28 द्वारा परिकल्पित विधायी शक्ति के विषय के भीतर आते हैं। हालांकि, बाजार अधिनियम भी उसमें वर्तमान में दिखाएगा, वस्तुओं की आपूर्ति का सौदा करेगा और वितरण के साथ-साथ व्यापार

और वाणिज्य बतायेगा क्योंकि यह अधिनियम के तहत निर्दिष्ट बाजार में की जाने वाली कृषि उपज की खरीद और बिक्री को विनियमित करना चाहता है। इस हद तक सूची।।। की प्रविष्टि 33 के प्रावधान व्यापार और वाणिज्य और वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण से संबंधित कानून के संबंध में राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियाँ खत्म कर देते हैं। एक बार हम समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 की ओर मुड़ें, तो हम पाते हैं कि उपखंड (बी) में सूचीबद्ध वस्तुओं के व्यापार और वाणिज्य का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के विषय पर हम खाद्य पदार्थों की सूचीबद्ध वस्तुओं को पाते हैं जिनमें शामिल हैं खाद्य तिलहन और तेल।”

सूची। की प्रविष्टि 52 के प्रयोजन के लिये 'उद्योग' शब्द का दायरे की रूमा पाल, न्यायाधिपति द्वारा आई. टी. सी. लिमिटेड की संविधान पीठ के फैसले में अपनी सहमति से विस्तार से जाँच की गई थी, जिसमें उपर्युक्त को संदर्भित किया गया, जिसमें यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

"126. संक्षेप में कहें तो: सूची। की प्रविष्टि 52 के प्रयोजन के लिये 'उद्योग' शब्द को टीका रामजी ने मजबूती से केवल

निर्माण या उत्पादन की प्रक्रिया के लिए सीमित कर दिया है। बाद के अन्य निर्णयों सहित संविधान पीठों के निर्णय ने फिर से पुष्टि की है कि टीका रामजी मामला आधिकारिक रूप से 'उद्योग' शब्द को परिभाषित करता है-जिसका अर्थ है निर्माण या उत्पादन की प्रक्रिया और इसमें उद्योग में उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल या उद्योग के उत्पादों के वितरण को शामिल नहीं किया गया है। सम्वैधानिक ढांचे और महत्व को देखते हुए न्यायिक प्राधिकरण के लिये 'उद्योग' शब्द के व्यापक अर्थ का प्रचार करने वाले एक तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है। किसी भी अन्य संदर्भ में शब्द का जो भी अर्थ हो, संवैधानिक संदर्भ में उसे 'निर्माण या उत्पादन' अर्थ के रूप में समझा जाए।

127. इस मामले में टीका रामजी में विकसित नकारात्मक परीक्षण को लागू करने से यह पता चलेगा कि सूची II की प्रविष्टि 24 में 'उद्योग' शब्द और इसके परिणामस्वरूप सूची I की प्रविष्टि 52 को सूची II की प्रविष्टियाँ 28 और 66 को शामिल करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है। जिन्हें स्पष्ट रूप से राज्य की अनन्य विधायी शक्तियों के भीतर क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, प्रविष्टि 28 बाजारों और मेलों से संबंधित है

और प्रविष्टि 66 वर्तमान संदर्भ में बाजार और मेलों के सम्बंध में शुल्क लगाने के अधिकार से सम्बंधित है। सूची। की प्रविष्टि 52 सूची॥ में प्रविष्टि 28 को ओवरराइड नहीं करती है, सूची॥ में प्रविष्टि 28 को सूची॥ की प्रविष्टि 24 के विपरीत प्रविष्टि 52 के अधीन नहीं बनाया गया है। बेलसुंड शुगर (सुप्रा) में इस न्यायालय भी इस तर्क को स्वीकार किया है कि सूची॥ की प्रविष्टि 28 अपने आप में संचालित होती है और सूची। की प्रविष्टि 52 में प्रदत्त उद्योग से संबंधित किसी भी कानून से प्रभावित नहीं हो सकती है।

128. यदि 'उद्योग' में 'बाजार और मेले' शामिल नहीं हैं तो यह परिभाषित करना महत्वपूर्ण है कि बाजार और मेलों का क्या अर्थ है। ' बाजार को 'सखती से' एक निश्चित समय और स्थान पर सार्वजनिक रूप से उजागर वस्तुओं या पशुधन की बिक्री या खरीदारी के लिए 'लोगों की बैठक या एकत्रीकरण' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।.... सामान्य कानून, मेले और बाजार भी फ्रेंचाइजी या उन वस्तुओं का निपटान करने के लिए खरीदार और विक्रेता का एक समूह आयोजित करने के अधिकार भी थे जिनकी फ्रेंचाइजी दी जाती है। इसमें बाजार में सामान बिक्री पर खरीदार द्वारा देय शुल्क या राशि वसूलने का अधिकार

शामिल था। जिस अर्थ में प्रविष्टि 28 में शब्द उपयोग किया गया है वह न केवल इस तरह के अधिकार बल्कि खरीदारों और विक्रेताओं का कॉनकोर्स सहित स्वयं बाजार और इन सभी का विनियमन प्रतीत होता। (इस न्यायालय द्वारा जोर दिया गया)“

26. उपर्युक्त निर्णयों का अवलोकन यह स्पष्ट करता है कि सूची। की प्रविष्टि 52 उत्पादन और उत्पादन की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। इसलिए, तत्काल मामले में, राज्य विधानमंडल के पास विवादित प्रावधान पर अधिनियम बनाने की क्षमता नहीं थी जो उन कृषि उपज पर भी बाजार शुल्क और विकास उपकर लगाने की मांग करते थे जो बिक्री के उद्देश्य से नहीं बल्कि निर्माण या आगे के प्रसंस्करण के उद्देश्य से बाजार में लाया जा रहा था। चूंकि राज्य विधानमंडल अधिनियम की विवादित धारा 27 (ग) (iii) का प्रावधान लागू करने के लिए सक्षम नहीं था अधिनियम की धारा को निरस्त किया जा सकता है। क्योंकि राज्य विधानमंडल द्वारा इसे ऐसा करने के लिए विधायी क्षमता के बिना अधिनियमित किया गया था।

बिन्दु संख्या 2 का उत्तर

27. प्वाइंट नं. 1 ऊपर में दर्ज निष्कर्षों और कारणों को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 27 (ग) (iii) में संशोधन की वैधता को बनाए रखने का विवादित सामान्य निर्णय और आदेश रद्द किया जाता है।

अधिनियम की धारा 27 (सी) (iii) को निरस्त कर दिया गया है। मांग की सूचना जारी करने की परिणामी कार्रवाई और अपीलार्थियों के विरुद्ध कोई भी आदेश निरस्त कर दिया जाता है। तथापि, धारा 27 (ग) (iv) को एतद्द्वारा बरकरार रखा जाता है। यह अदालत यह बहुत स्पष्ट करती है कि खरीदार को यह साबित करना होगा कि कृषि उपज अन्य राज्य से लाई जाती है जो एक अंतरराज्यीय बिक्री है, और के वस्तुओं की बिक्री अधिनियम, 1930 प्रावधानों के अनुसार है।

28. उपरोक्त शर्तों में इन दीवानी अपीलों की अनुमति है। कोई हर्जाना नहीं।

निधि जैन अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक बृजेश कुमार, अधिवक्ता उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।